विचार बिन्दु

संसार के दुःखियों में पहला दुःखी निर्धन है। उससे दुःखी वह है जिसे किसी का ऋण चुकाना हो। इन दोनों से अधिक दुःखी वह है, जो सदा रोगी रहता हो और सबसे दुःखी वह है, जिसकी पत्नी दुष्टा हो। –विदुरनीति

गहलोत सरकार के समय राजस्थान में वित्त प्रबंधन के हाल ठीक नहीं

राजस्थान के वित्तीय हालात पर सीएजी की नई सालाना रिपोर्ट आ गई है। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के सरकार के लेखों और खातों का विश्लेषण किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष आने वाली सीएजी की रिपोर्टें राज्य विधान सभा में प्रस्तुत की जाती है। उनकी टिप्पणियों पर विधानसभा की जनलेखा समिति में चर्चा होती है जिसमें प्रसासनिक अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा जाता है। मगर आम तौर पर विधानसभा के गिने-चुने सदस्य ही इन रिपोर्टों पर नज़र डालते हैं। उन्हें गौर से पढ़ने और उसके आधार पर सदन में बहस करने की कोई जहमत नहीं उठाता। ऐसे में आम जन से कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वह ऐसी रिपोर्टें पढ़ कर राजकोष के प्रबंधन के बारे में गहराई से समझे और अपने उन प्रतिनिधियों से सवाल करे जिन्हें उसने अपना वोट देकर संसद और विधान सभाओं में भेजा है। सीएजी की यह रिपोर्ट हमें चिंता में डालती है, क्योंकि वह कहती है कि सरकार की प्राप्तियों और व्यय अर्थात आमद और खर्च के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया जैसे हालात बन रहे हैं। संवैधानिक संस्था की यह रिपोर्ट राजकोषीय तनाव का स्पष्ट संकेत देती है। जैसे कि इस रिपोर्ट को पढ़ कर हम पाते हैं कि राजस्थान सरकार की राजस्व प्राप्तियां 2018-19 से 2022-23 तक 1,37,873 करोड़ से बढ़कर 1,94,988 करोड़ हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार की आमदनी में औसत वार्षिक वृद्धि की दर 9.75 प्रतिशत रही। इन राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2018-19 में 14.53 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 15.31 प्रतिशत हो गया, जो केंद्र सरकार से मिला। रिपोर्ट कहती है कि यह हालत राज्य की केंद्र पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाती है। हालांकि इसका एक सकारात्मक पहलू यह माना जा सकता है कि राज्य में इस दौरान विपक्ष की सरकार रही और उसको अनुदान देने में केंद्र सरकार ने भेद-भाव नहीं किया। हालांकि ऐसे राजनैतिक आरोप अमूमन लगते रहे हैं। राजस्थान को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्र के हिस्से के रूप में 14,554 करोड़ मिले।

इसे समझने के लिए किसी वित्तीय ज्ञान की डिग्री की जरूरत नहीं होती कि घाटे से गाड़ी नहीं चलती। जब राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता होती है तो उसके परिणामस्वरूप राजस्व खाते में घाटा होगा ही। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2018-19 में 28,900 करोड़से बढ़कर चालू वर्ष में 31,491 करोड़ रुपये का हो गया। इसे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो वह 2018-19 में यह घाटा 2.23 प्रतिशत था जो बढ़ कर 3.17 प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पूंजी खाते पर केवल 19,798 करोड़ खर्च किए। पूंजी खाता वह होता है जिसमें राज्य की संपत्ति का निर्माण होता जो राज्य को आमदनी देती है। यह पूंजीगत खर्च वर्ष 2022-23 में कुल व्यय का केवल 8.03 प्रतिशत था। यह गौर करने की बात है कि पूंजीगत व्यय कुल उधार का मात्र 5.10 प्रतिशत था। इसका खुलासा करते हुए रिपोर्ट बताती है कि सरकार रुपये उधार लेकर उसका उपयोग मुख्य रूप से पूंजी निर्माण/विकास गतिविधियों पर करने के बजाय वर्तमान खपत को पूरा करने और पुरानी उधारी चुकाने के लिए कर रही है। उधार लेकर उधारी चुकाने की नौबत हो तब तो सरकार से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह अपनी फिजूलखर्ची तो अंकुश लगाए। फिजूलखर्ची आलीशान सरकारी कार्यालयों के भवन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के ऐश-ओ-आराम पर ही नहीं होती बल्कि गरीबों की मदद के नाम पर मुफ़्त सुविधाओं की बंदर-बांट पर भी होती है। प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी लोकतंत्र में सरकारें बेहतर शासन प्रशासन देकर आम लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने में असफल रहने के बाद मुफ़्त की चीजें बांट कर लोगों के वोट पाने की जुगत में लगी रहती हैं। यह सारी दुनिया जानती है कि खुले बाज़ार की इफ़रात वाली अर्थव्यवस्था में बाज़ार तो खूब दमकता है मगर नई बन रही संपत्ति केवल 21 प्रतिशत आबादी के हाथों में सिमटी रहती है। सरकारें आम लोगों को अर्थव्यवस्था में मजबूत बनाने के कठिन रास्ते पर चलने के बजाय बाजार की ताकतों के इशारों पर चलने लगती हैं। जबकि अधिकाश संपत्ति ऊपर की 21 प्रतिशत आबादी में बंट जाती है तब सरकार सबसे नीचे की आबादी को मुफ़्त राशन, मुफ़्त पानी, मुफ़्त पेंशन देकर अपने वोट बचाना चाहती हैं मगर सार्वजनिक शिक्षा तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य से अपने हाथ खींचते हुए उन्हें निजी क्षेत्र के हवाली करती जाती है। इससे देश की 80 प्रतिशत आबादी गरीबी में रहने को अभिशप्त हो जाती है। जब सरकारें राजकोष से रेवड़ियां बांटने में रस लेने लगती है तब राज्य की वित्तीय व्यवस्था बिगड़ती चली जाती है। मगर क्योंकि सरकार नोट छाप सकती है और उधार लेकर तथा करों से अपनी आय बढ़ाने के इंतजाम करके काम चला सकती हैं इसलिए सरकारों की वित्तीय व्यवस्था ढहती नहीं। मगर वित्तीय व्यवस्था तनाव में जरूर आ जाती है जिसका खामियाजा विभिन्न करों की बढ़ोतरी तथा सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट के रूप में सामने आता है। इस बार की सीएजी रिपोर्ट राजस्थान की जिस वित्तीय तनाव को उजागर करती है उससे प्रत्येक नागरिक का चिंतित होना लाजिमी है।

इसे समझने के लिए किसी वित्तीय ज्ञान की डिग्री की जरूरत नहीं होती कि घाटे से गाड़ी नहीं चलती। जब राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता होती है तो उसके परिणामस्वरूप राजस्व खाते में घाटा होगा ही। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2018-19 में 28,900 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष में 31,491 करोड़ रुपये का हो गया। इसे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो वह 2018-19 में यह घाटा 2.23 प्रतिशत था जो बढ़ कर 3.17 प्रतिशत हो गया।

रिपोर्ट बताती है कि राज्य की सरकार अपने खर्चों पर अंकुश नहीं रख सकी है। राज्य के कुल खर्चे 2018-19 में 1,87,524 करोड़ रुपये थे, वे 2022-23 में 31.42 प्रतिशत बढ़कर 2,46,452 करोड़ हो गये। दूसरी तरफ सरकार की राजस्व प्राप्तियां 2021-22 में 15.10 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 13.79 प्रतिशत हो गईं। प्रतिबद्ध व्यय के अलावा, 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय के 20.38 प्रतिशत से बढ़कर 28.49 प्रतिशत हो गया, जो एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। इंफ्लेक्सिबलव्यय 2021-22 में 63,251 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 64,525 करोड़ रुपये हो गया, जो 2.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। एक साथ लिया जाए तो 2022-23 में प्रतिबद्ध और इंफ्लेक्सिबल व्यय 1,80,282 करोड़ था जो राजस्व व्यय का 79.60 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और इंफ्लेक्सिबल व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूंजी निर्माण के लिए कम लचीलापन देती हैऔर उसका सबसे अधिक असर गरीब पर होता है। गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, जो 2018-2019 में 21,540 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 26,166 करोड़ रुपये हो गई। इस अवधि के दौरान कुल सब्सिडी में बिजली क्षेत्र की सब्सिडी का हिस्सा 96.20 प्रतिशत से लेकर 98.44 प्रतिशत तक रहाजो बिजली सुधार के कार्यक्रमों के टिकाऊ नहीं होने को ही दर्शाता है। रिपोर्ट यह भी याद दिलाती है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना था या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। मगर ऐसा नहीं हो पाया है। सीएजी का कहना है कि लगातार दसवें वर्ष, राज्य सरकार शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही। राजकोषीय रुझानों के अनुसार, राज्य की वित्तीय स्थिति काफी तनावपूर्ण है क्योंकि राजस्थान का सार्वजनिक ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2018-19 में 25.59 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 26.63 प्रतिशत हो गया है। यह दर्शाता है कि निकट भविष्य में ऋण स्थिरीकरण में मुश्किल हो सकता है। सीएजी की टिप्पणी है कि सरकारी खातों के विश्लेषण और उसके रिणाम के अनुसार, राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति में देनदारियों (ऋण, गारंटी, सब्सिडी, आदि) की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो ऋण स्थिरीकरण और ऋण स्थिरता के लक्ष्य के लिए जोखिम पैदा करती है।

कोई निजी संस्थान ऐसा करे तो सरकार उसे पकड़ेगी, मगर सरकार ही जब ऐसा करे तब क्या किया जा सकता है! राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान 3,000 करोड़ की जीपीएफ जमाराशि, जो कर आय नहीं है, में से 1,000 करोड़ रुपये की राशि जिसे 'कार्मिक कल्याण कोष' में स्थानांतरित करना था उसे अपनी राजस्व प्राप्तियों में स्थानांतरित कर दिए। वर्ष 2021-22 के दौरान भी, 1000 करोड़ की जीपीएफ जमाराशि को राजस्व प्राप्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया था। सरकार ने ऐसा अपनी राजस्व प्राप्तियों को बढ़ा कर दिखाने और राजकोषीय घाटे को कम दर्शाने के लिए किया था। इससे सरकार की विश्वसनीयता की कमी होगी। बजट विश्वसनीयता के समग्र मूल्यांकन से पता चलता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और मूल बजट के बीच तथा वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के बीच विचलन 10 प्रतिशत से कम था, फिर भी विभिन्न बजट अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और उससे भी अधिक विचलन देखने को मिलता है। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कई मामलों में पूरक अनुदान ऐसे थे, जिनमें खर्चा मूल अनुदान के बराबर भी नहीं हुआ। सीएजी ने ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया है जिस पर अमल किया जाना जरूरी है। इसके अलावा सरकार में बढ़ती हुई एक नई प्रवृत्ति की ओर भी सीएजी ने ध्यान दिलाया है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों के माध्यम से उधार लेती है, जो राज्य की समेकित निधि में नहीं आता, लेकिन बजट के माध्यम से चुकाया जाता है। वर्ष 2022-23 में, राज्य सरकार ने ऑफ बजट उधार के ब्याज और पुनर्भुगतान के लिए 1,279.39 करोड़ की सहायता अनुदान दिया। यह सरकार द्वारा उधार पर चुकाए गए पुनर्भुगतान और ब्याज के अतिरिक्त था। इन रिपोर्टों के बावजूद सरकार में सब चलता है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

जाति प्रथा और धार्मिक वैमनस्य के सख्त खिलाफ थे स्वामी विवेकानंद

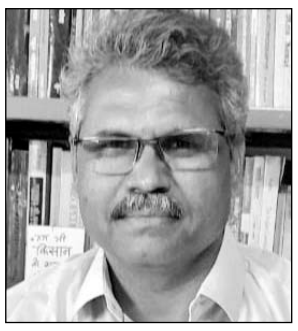

डॉ. रमेश बैरवा

"उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए" के उद्घोष के जरिए युवाओं को विशेष रूप से उद्वेलित करने वाले, तथा सामाजिक समानता, सांप्रदायिक सद्भाव एवं समाजवाद के प्रबल पक्षधर, अपने समय के विद्रोही संन्यासी स्वामी विवेकानंद को सादर नमन। यह व्याख्यान मूलत: 'सिलेक्टेड वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद' में संकलित विवेकानंद के भाषण एवं विचारों पर आधारित है, इनके सामाजिक चिंतन पर केंद्रित है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद नाम तो उन्होंने सन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपनाया, जब वे 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। विवेकानंद पर अपनी माता और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का गहरा असर था। 1897 में विवेकानंद ने कोलकाता के पास बेलूर में प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की अल्पायु में ही विवेकानंद का देहांत हो गया।

विवेकानंद के जीवन दर्शन के मुख्यत: तीन स्त्रोत थे-प्रथम, वेदों तथा वेदांत की परंपरा; द्वितीय, गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका संपर्क एवं संवाद एवं तृतीय, उनके अपने जीवन का अनुभव। इन तीनों ही स्त्रोतों के माध्यम से विवेकानंद के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का निर्माण हुआ जो अंततोगत्वा उनके विचारों के आधार स्तंभ बने।

विवेकानन्द जाति-व्यवस्था का अंत चाहते थे। विवेकानन्द अपने समय से आगे थे। जिस समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता जाति प्रथा की स्पष्ट रूप से आलोचना करने में हिचकिचा रहे थे, विवेकानन्द ने शोषणकारी जाति प्रथा के खिलाफ दृढ़ता से आवाज उठाई। उन्होंने इसकी वंशानुगतता को बकवास कहा और निचली जातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा।

विवेकानन्द उच्च जाति के युवाओं को संबोधित करते हुए उनके जातीय श्रेष्ठता और छुआछूत संबंधी विचारों की तीव्र भर्त्सना करते हैं:-"और तुम लोग क्या हो?...पूरी ज़िंदगी केवल बेकार की बातें करने वाले, व्यर्थ बकवास करने वाले...अपनी खोपड़ी में सैकड़ों वर्षों के अंधविश्वास का कूड़ा-करकट भरे बैठे, सैकड़ों वर्षों से केवल खान-पान की छुआछूत के विवाद में अपनी सारी शक्ति नष्ट करने वाले, जिनकी सारी इन्सानियत को युगों के सामाजिक अत्याचार ने कुचल दिया है।" स्वामी विवेकानंद ने ब्राह्मणों के जन्म आधारित श्रेष्ठता के दम्भ की कड़ी आलोचना की और उसे महज 'मिथ्या' कह कर खारिज कर दिया।

4 जुलाई 1897 को अल्मोड़ा से भगिनी निवेदिता को लिखा विवेकानन्द का पत्र यह साबित करता है कि वे जो कहते थे वही करते भी थे। उस पत्र में वे लिखते हैं कि बुद्ध के जमाने के बाद पहली बार उनके आश्रम में ब्राह्मण युवा बिना किसी जाति-भेद के रोगियों की सेवा कर रहे हैं। विवेकानन्द ने भारत की भयंकर गरीबी और पतन के लिए अंग्रेजी उपनिवेशवाद से ज्यादा जाति-व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया।

11 सितंबर 1893 को शिकागो (अमेरिका) में हुए धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपने ऐतिहासिक वक्तव्य के माध्यम से भारत की एक वैश्विक सोच को सामने रखते हुए हिंदू धर्म का उदारवादी चेहरा दुनिया के सामने रखा था। पूरी दुनिया ने उनके भाषण को सराहा था। विवेकानंद का हिंदू धर्म, पाखंड और कर्मकांड विरोधी होने के साथ दलित, वंचित और श्रमिक वर्ग को न्याय दिलाने वाला सर्वसमावेशी था। इसमें भारत की आध्यात्मिकता और भौतिक विकास की मिली जुली ललक थी। इसमें सांप्रदायिक और जातीय नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं थी। यद्यपि वे समकालीन राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन उनका धर्म सामाजिक सत्ता से लगातार टकराता था। यही कारण है कि राजनीति के प्रति विरक्ति का भाव रखने वाले विवेकानंद कई राजनीति करने वालों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनते रहे।

धर्म और देशभक्ति की आड़ में समाज और सत्ता पर वर्चस्व कायम रखने का इरादा रखने वाली विवेकहीन ताक़तें बेशर्मी के साथ स्वामी विवेकानंद को अपनी विचार-परंपरा का पुरखा बताकर इन्हें हथियाने की फूहड़ कोशिशें करती रही हैं और अब भी कर रही हैं, ताकि विवेकानंद की प्रखर सामाजिक चेतना का विभाजनकारी संकीर्ण राष्ट्रवाद के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सके। चूँकि इस ख़तरे का अंदाज़ा विवेकानंद को भी था, लिहाज़ा उन्होंने अपने प्रसिद्ध व्याख्यान कास्ट, कल्चर एंड सोशलिज़्म' में कहा था- "कुछ लोग देशभक्ति की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन मुख्य बात है-हृदय की भावना। यह देखकर आपके मन में क्या भाव आता है कि न जाने कितने समय से देवों और ऋषियों के वंशज पशुओं जैसा जीवन बिता रहे हैं? देश पर छाया अज्ञान का अंधकार क्या आपको सचमुच बेचैन करता है?...यह बेचैनी ही आपकी देशभक्ति का पहला प्रमाण है।"

चूँकि विवेकानंद राजनेता नहीं बल्कि संन्यासी थे-समाज विज्ञानी संन्यासी, लिहाज़ा वह हिंदू समुदाय की ख़ूबियों और ख़ामियों से भलीभाँति परिचित थे। हिंदू समाज में आज जो कट्टरता व्याप्त है, उसके ख़तरे को विवेकानंद की दी हुई चेतावनी से भी समझा जा सकता है। उन्होंने अपने समय के हिंदू कट्टरपंथियों और पाखंडी धर्माचार्यों को ललकारते हुए कास्ट, कल्चर एंड सोशलिज़्म' में ही कहा है-

"शूद्रों ने अपने हक माँगने के लिए जब भी मुँह खोला, उनकी जीभें काट दी गईं। उनको जानवरों की तरह चाबुक से पीटा गया। लेकिन अब आप उन्हें उनके अधिकार लौटा दो, वरना जब वे जागेंगे और आप (उच्च वर्ग) के द्वारा किए गए शोषण को समझेंगे, तो अपनी फूँक से आप सब को उड़ा देंगे। यही (शूद्र) वे लोग हैं, जिन्होंने आपको सभ्यता सिखाई है और ये ही आपको नीचे भी गिरा देंगे। सोचिए कि किस तरह शक्तिशाली रोमन सभ्यता गॉलों के हाथों मिट्टी में मिला दी गई।"

विवेकानंद जीवन में धर्म और अध्यात्म को बड़ा महत्व देते हैं। लेकिन धार्मिक संकीर्णता और रूढ़िवाद के सख्त खिलाफ थे। वे मत-मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर को गौण मानते थे। धर्म की आड़ में अंधश्रद्धा के खिलाफ थे। तर्क और विवेक को सर्वोच्च स्थान देते थे। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की तरह विवेकानंद ने धार्मिक संकीर्णता का विरोध करते हुए सर्वधर्म सम्भाव अर्थात सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया। 10 जून 1898 में नैनिताल के अपने एक मुस्लिम मित्र मोहम्मद सरफराज हुसैन को लिखे पत्र में स्वामी जी ने लिखा कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों- हिंदू धर्म और इस्लाम का संगम ही एकमात्र उम्मीद है।

विवेकानंद ने कहा है कि भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद देश की आबादी के एक बड़े हिस्से ने इस्लाम क़ुबूल कर लिया था, लेकिन साथ ही वह कहते हैं कि यह सब तलवार के ज़ोर से नहीं हुआ था। धार्मिक नफ़रत के सख्त ख़िलाफ़ थे स्वामी विवेकानंद। हिंदुत्व एवं राष्ट्रवाद की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रतभरी विचारधारा को सही ठहराने के लिए कुछ संगठन स्वामी विवेकानंद के नाम का इस्तेमाल लंबे समय से करते आ रहे हैं, उनके समय में भी करते थे। लेकिन चूँकि ऐसे लोगों की क्षुद्र मानसिकता और मुसलमानों के प्रति उनकी द्वेष-भावना से विवेकानंद भलीभाँति परिचित थे, लिहाज़ा उन्होंने कहा था- "इस अराजकता और कलह के बीच भी मेरे मस्तिष्क में संपूर्ण भारत की जो तस्वीर उभरती है, वह शानदार और अद्वितीय है, उसमें वैदिक दिमाग और इस्लामिक शरीर होगा।" कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद अगर आज ज़िंदा होते तो उनकी नसीहतें सुनकर हिंदू कट्टरता के प्रचारक विवेकानंद को भी सूडो सेकुलर या हिंदू विरोधी क़रार दे रहे होते! विवेकानंद को हजम करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए हम कहते हैं, अपने-अपनेविवेकानंद! स्वामी विवेकानंद अमर रहे।

(यह लेख विवेकानंद जयंती के अवसर पर दिए व्याख्यान के प्रमुख अंशों पर आधारित है)

–डॉ. रमेश बैरवा,
राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर एवं प्रदेश संयोजक, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रुक्टा डेमोक्रेटिक।

दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित पाबू पाठशाला को आर्य समाज स्कूल में मर्ज किया

स्कूल में मर्ज के फैसले ने 61 दिव्यांग छात्रों के भविष्य को अनिश्चितता में डाला

- **अभिभावक अपने बच्चों को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे**
- **अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के कारण अभिभावक निराश लौटे**

बीकानेर, (निसं)। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित पाबू पाठशाला को आर्य समाज स्कूल में मर्ज करने के फैसले ने 61 दिव्यांग छात्रों के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है।

इस फैसले से चिंतित अभिभावक अपने बच्चों को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल को यथावत रखने की मांग की, लेकिन अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के कारण वे निराश लौटने को मजबूर हो गए।

अभिभावकों का कहना है कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं और अनुकूल वातावरण से युक्त इस स्कूल का विलय उनके बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इनमें से कई बच्चे ऐसी विशेष आवश्यकताओं वाले हैं, जिन्हें सामान्य स्कूलों में पढ़ाई करने में कठिनाई होगी। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि इस फैसले को वापस लिया जाए और पाबू पाठशाला को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखा जाए। उनका कहना है कि यदि यह फैसला जल्द नहीं बदला गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश से पहले स्कूल की जमीनी हकीकत भी नहीं देखी जिस जगह स्कूल का एकीकरण किया है वहां रेंप भी नहीं है।

बघेरे ने किसान पर हमला किया

झिलाय, (निसं)। सोमवार की रात गांव खेड़ीमानपुर में एक युवक पर बघेरे ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। परिवारजनों ने उसका गांव में ही उपचार करवाया। लोगों ने बघेरा की सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जंगली जानवर के पग मार्क देखे। ग्रामीणों ने बताया कि कालू शर्मा रात खेत पर रखवाली कर रहा था। घर वापसी के दौरान बघेरा ने उस पर हमला कर दिया। सूचना पर सरपंच सांवरमल मीणा, एसीएफ अनुराग महर्षि, रैंजर धारिलाल व टोंक लाईन रैंजर कालूराम मौके पर पहुंचे।

देशभर में दौड़ रहे जोधपुर रेलवे वर्कशॉप में बने एन.एम.जी.एच.एस. डिब्बे

- **एनएमजीएचएस डिब्बे दरअसल ट्रेनों के वो कोच होते हैं, जिनका 25 वर्षों तक उपयोग लेने के बाद रेलवे यात्री सेवा की दृष्टि से रिटायर कर चुका होता है**

जोधपुर, (कासं)। उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेलवे वर्कशॉप में खासतौर से निर्मित एनएमजीएचएस ट्रेन के डिब्बे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बिना खिड़की और और बंद दरवाजों वाली एनएमजीएचएस ट्रेन में माल लदान के प्रयोग में लाए जाने वाले एनएमजीएचएस डिब्बे दरअसल ट्रेनों के वो कोच होते हैं जिनका 25 वर्षों तक उपयोग लेने के बाद रेलवे यात्री सेवा की दृष्टि से रिटायर कर चुका होता है, लेकिन रिटायर हो चुके कोच को भी मॉडिफाई कर रेलवे उसकी उपयोग अवधि 10 वर्ष और बढ़ा देता है जिसे रेल की भाषा में एनएमजीएचएस (न्यूली मॉडिफाईड गुड्स साइड) कहा जाता है। भारतीय रेलवे के प्रमुख जोधपुर रेलवे वर्कशाप में रेलवे के रिटायर हो चुके डिब्बों को बहुद्देश्यीय एनएमजीएचएस कोचों में तब्दील करने का काम पिछले चार वर्षों से चल रहा है तथा वर्कशॉप द्वारा अब तक इस तरह के 101 डिब्बे तैयार करके राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है तथा रेलवे बोर्ड से प्राप्त लक्ष्यों के अनुरूप यह कार्य निरंतर जारी है।

जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह का इस संबंध में कहना है कि रेलवे में माल लदान की दृष्टि से एनएमजीएचएस डिब्बों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा निजी कंपनियों की ओर से सुरक्षित माल लदान के लिए इनकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि रेल पटरियों पर 25 वर्षों तक दौड़ने के बाद आईसीएफ कोच को पैसेंजर ट्रेन से रिटायर कर दिया जाता है और ऐसे डिब्बों को एनएमजीएचएस रैक के नाम से ऑटो कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी सभी खिड़कियां और दरवाजे सील कर दिए जाते हैं।

पंकज कुमार सिंह का कहना है इस वैगन को इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि इसमें कार, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक और दुपहिया वाहनों को आसानी से लोड-अनलोड किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस तरह के डिब्बे में रेफ्रिजरेटर की तरह रैक्स सिस्टम भी विकसित किया गया है जिससे इसमें सब्जियों का लदान भी किया जाता है। डिब्बे को मॉडिफाई करने के दौरान उसके भीतर से सभी सीटों, लाइट और पंखों को हटा कर लंबा हॉलनुमा आकार दे दिया जाता है और रोशनी के लिए सिर्फ डिब्बे की छत पर होल रखे जाते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट की आशंका न हो। कोच के पिछले हिस्से में एक बड़ा दरवाजा बनाया जाता है ताकि आसानी से सामान लोड या अनलोड किया जा सके।

मुख्य कारखाना प्रबंधक मनोज जैन ने बताया कि जोधपुर रेलवे वर्कशॉप से पहला एनएमजी कोच 23 नवंबर 2020 को तैयार होकर निकला, जिसकी सफलता को देखते हुए उसे 2020-21 में 35, 2021-22 में 10 और 2023-24 में 29 तथा चालू वित्त वर्ष में 120 रिटायर आईसीएफ डिब्बों को एनएमजीएचएस डिब्बों में तब्दील करने का लक्ष्य दिया गया है जिसमें से 14 जनवरी तक 27 एनएमजीएचएस डिब्बे तैयार कर मंडलों को उपयोग के लिए दे दिए गए हैं।

सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने जानकारी दी कि एक रिटायर हो चुके आईसीएफ डिब्बे को वर्कशॉप में एनएमजीएचएस डिब्बे में तब्दील करने में करीब साढ़े ग्यारह लाख रुपए की लागत आती है और इसे सामान्य तौर पर 16 दिनों में तैयार कर दिया जाता है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए गार्ड एसएलआर, जनरल और स्लीपर डिब्बे ही काम में लिए जाते हैं।

राशिफल बुधवार 22 जनवरी, 2025

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2081, स्वाती नक्षत्र रात्रि 2:34 तक, शूल योग रात्रि 4:37 तक, कौलव करण दिन 3:19 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मिथुन, बुध-धनु, गुरू-वृष, शुक्र-कुम्भ, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज महापात योग रात्रि 4:50 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:54 तक, शुभ 11:19 से 12:38 तक, चर 3:17 से 4:37 तक, लाभ 4:37 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:20, सूर्यास्त 5:56

मेष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

वृश्चिक
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। वाणी पर संयम रखना ठीक रहेगा।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।